1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	121409	113047	17642	0
6.	हिमाचल प्रदेश	284053	3340	2934	261
7.	जम्मू व कश्मीर	456000	450000	0	0
8.	कर्नाटक	275298	113973	17742	777
9.	केरल	133354	62941	57904	7128
10.	मध्य प्रदेश	294570	176200	19788	25707
11.	महाराष्ट्र	704329	524645	39195	26283
12.	मणिपुर	1830	1682	96	72
13.	उड़ीसा	173926	146100	42623	46568
14.	पंजाब	138090	101838	10048	0
15.	राजस्थान	618712	433738	26688	11648
16.	तमिल नाडु	179767	143537	54480	97
17.	त्रिपुरा	1995	1599	256	359
18.	उत्तर प्रदेश	531755	361527	212656	711
19.	पश्चिम बंगाल	1262777	913389	741094	384033

Most Backward Areas

4022. SHRI JAGADISH JANI : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have identified 100 most backward areas for their all rural development ;

(b) if so, the State-wise details of those areas ;

(c) the details of the schemes prepared for the development of those areas; and

(d) the funds earmarked for their development ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL) : (a) No, Sir.

(b) to (d) Does not arise.

मध्य प्रदेश में पेयजल

4023. श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य के अधिकांश भागों में प्रदूषित पेय जल के कारण "नारू" नाम की महामारी फैल गई है ; और

(ख) इन लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है ; और

(ग) तत्संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1-1-1992 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश में गिनी कृमि से प्रभावित 20 गांवों में गिनी कृमि से प्रभावित 120 मामले थे ।

(ख) और (ग) इन 26 गांवों में सभी सीढ़ीदार कुंओं को स्वच्छ कुंओं में बदल दिया गया है । पूरे राज्य में, 3217 सीढ़ीदार कुंओं में से 3172 कुंओं को स्वच्छ जल स्रोतों में बदल दिया गया है । स्वच्छ पेयजल की सप्लाई, स्वास्थ्य शिक्षा और संचार, घरेलू/पर्यावरण संबंधी स्वच्छता, प्रशिक्षण, आधारभूत ढांचा विकास आदि के लिए

25.08 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली एक समन्वित परियोजना को अनुमोदित किया गया है। इसमें से 11.71 करोड़ रुपए केंद्रीय सरकार द्वारा अपनी 8.91 करोड़ रुपये यूनिसैफ द्वारा, 3.91 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा अपनी निजी निधियों में से वहन किए जायेंगे और शेष 0.55 करोड़ रुपये लाभार्थियों के योगदान से प्राप्त किए जायेंगे। इस परियोजना के लिए 3 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में रिलीज किए जा चुके हैं।

गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाना

4024. **श्री राघव जी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 29 फरवरी, 1992 की स्थिती के अनुसार ऐसे गांवों की राज्य वार संख्या कितनी है जितनी संख्या 1991 की जनगणना के अनुसार एक हजार थी लेकिन पक्की सड़कों से नहीं जुड़े हुए थे ;

(ख) क्या देश में सड़कों के असंतुलित विकास को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त गांवों को प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़ने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है, और

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जाएगी, और यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) 1991 की जनगणना के अनुसार, एक हजार और उससे अधिक लोगों की आबादी वाले गांवों की राज्यवार संख्या के बारे में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं हुई है तथापि, सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक एक हजार और उससे अधिक की आबादी वाले गांवों, जिन्हें पक्की सड़कों से जोड़ा नहीं गया है, की संख्या के राज्यवार आंकडे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सड़कों का निर्माण, जिनमें ग्रामीण सड़कें भी शामिल हैं, राज्य का विषय हैं और इसके लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य योजनाओं में निधियां उपलब्ध कराई जाती ।

विवरण

	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत सातवीं योजना के अंत तक 1000 और उससे अधिक की आबादी वाले गांवों की संख्या जिन्हें पक्की सड़कों से नहीं जोड़ा गया है।
1.	आंध्र प्रदेश	2286
2.	अरुणाचल प्रदेश	13
3.	असम	40
4.	बिहार	6182
5.	गोआ	--
6.	गुजरात	406
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	70
9.	जम्मू व कश्मीर	174
10.	कर्नाटक	2202
11.	केरल	--
12.	मध्य प्रदेश	2080
13.	महाराष्ट्र	864
14.	मणिपुर	--
15.	मेघालय	--
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	16
18.	उड़ीसा	1034
19.	पंजाब	--
20.	राजस्थान	1147
21.	सिक्किम	9
22.	तमिलनाडु	561
23.	त्रिपुरा	83
24.	उत्तर प्रदेश	5360
25.	पश्चिम बंगाल	4022
26.	अन्डमान निकोबार द्वीप समूह	--
27.	चंडीगढ़	--
28.	दादर व नागर हवेली	4
29.	दमन व दीव	--
30.	दिल्ली	--
31.	लक्षद्वीप	--
32.	पांडिचेरी	--